विवरण-2

तीर्थ पर्यटन पर समिति द्वारा विकास के लिए शिनाख्त किए गए केन्द्र

क्रम सं.	राज्य	केन्द्र/स्थान
1.	असम	कामाख्या
2.	बिहार	बोधगया और पटना साहिब
3.	गुजरात	द्वारिका, पालिटाना और उदवाड़ा (वापी के पास)
4.	हिमाचल प्रदेश	पौंटा साहिब और ज्वाला जी
5.	जम्मू और कश्मीर	माता वैष्णौदेवी
6.	कर्नाटक	श्रृंगेरी और गुलबर्गा
7.	केरल	गुरुवायूर
8.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
9.	महाराष्ट्र	नान्देह, शिर्डी और ज्योतिबा
10.	उड़ीसा	जगन्नाथ पुरी
11.	राजस्थान	अजमेर शरीफ
12.	तमिलनाडु	रामेश्वरम्
13.	उत्तर प्रदेश	(1) बद्रीनाथ-केदारनाथ-गंगोत्री यमुनोत्री
		(2) बर्सांना-नन्दगांव-गोकुल-मथुरा-वृंदावन-गोवर्धन

बौद्ध स्थलों के विकास हेतु निधियां

2166. **श्री राघवजी:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास हेतु विभिन्न देशों से वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त राशि में से कौन-कौन से तीर्थ स्थलों पर प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) यदि कोई राशि व्यय नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने, बौद्ध स्थलों के विकास के लिए, विदेशी आर्थिक सहयोग कोष, जापान के साथ आसान शर्तों के दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(1) उत्तर प्रदेश और बिहार में अभिनिर्धारित यात्र-परिपथों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 9.244 बिलियन जापानी येन (बाद में पुनरीक्षित 7.76 बिलियन जापानी येन)। उत्तर प्रदेश में अभिनिर्धारित किए गए स्थान, सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा और श्रावस्ती हैं तथा बिहार में बोधगया, नालन्दा, राजगीर और वैशाली स्थान शामिल हैं।

(2) महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा के लिए संरक्षण और पर्यटन विकास योजना हेतु 3.75 बिलियन जापानी येन।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित जापानी ट्रस्ट फण्ड के माध्यम से यूनेस्को परियोजना के तहत सांची और सतधारा (मध्य प्रदेश) में बौद्ध स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 60,000 अमेरिकी डालर प्राप्त किए हैं।

(ख) और (ग) विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से ऋण अग्रिम रूप में नहीं मिलता। कार्यान्वयन अभिकरणों को पहले अपने स्वयं के संसाधनों से खर्च करके फिर विदेशी आर्थिक सहयोग कोष से प्रतिपूर्ति का दावा करना होता है। विदेशी आर्थिक सहयोग कोष द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण, स्मारकों के आसपास भू-दृश्यांकन, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण करने और विद्युत और जल आपूर्ति को बढ़ाने जैसे विभिन्न घटकों पर किए गए कार्य के लिए लगभग 42.76 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गई है। महाराष्ट्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वन रोपण और संरक्षण कार्य पर क्रमश: 51 लाख और 24 लाख रु. खर्च किए हैं। राष्ट्रीय हवाईपत्तन प्राधिकरण ने भी अजंता और एलोरा परियोजना के अंतर्गत औरंगाबाद हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 253.67 लाख रुपए खर्च किए हैं। अजंता और एलोरा परियोजना के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सांची और सतधारा परियोजना के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान 8,08,299.80 रुपए खर्च किए हैं।

Proposal to build new civilian airport in Goa

2167. **SHRI JOHN F. FERNANDES:** Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from Goa Government to build new Civilian Airport in Goa in private sector sponsored by NRI;

(b) if so, when such proposal was received and the response of the Central Government; and

(c) what are the financial implication of this project and the site earmarked in the proposal and its location in Goa?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Use of Sub-standard Material for Building Water Sports Complex in Goa

2168. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government are aware of sub-standard construction material used to build the Water Sports Complex at Dona Paula, Goa, wherein the contractors in collusion with local Government staff used local beach sand, instead of construction sand of ticker gradient as a result, this cement work will be masked out in monsoons;

(b) what is the total amount of this project and how much amount has been paid to the contractors; and

(c) whether any work guarantee has been taken for this project?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) No, Sir. During the year 1993-94 an amount of Rs. 13,84,415/- was sanctioned to the Govt. of Goa who have paid Rs. 4,51,238/- to the contractor for undertaking the civil works such as land filling and land development for tented accommodation at the National Institute of Water Sports. Quality control tests such as testing of sand, aggregates used for the construction of drain have been carried out by PWD, Goa.

However, they found that some of the work was unacceptable and the same has been asked to be demolished as per the clause of the contract between PWD Goa and the contractor.

Night stop service facility for aircraft at Coimbatore

2169. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government would come forward to provide Night Stop Servicing facility for A-320 aircraft at Coimbatore so as to upgrade the Airport there;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) Indian Airlines already night stops two A-320 aircraft at Bangalore. Another sub-base for night stop at Coimbatore is not considered necessary, at present.

Involvement of Private Sector to promote Tourism in the country

2170. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have asked some States and Union Territories to involve the private sector and tour operators to promote tourism in the country;

(b) if so, the details of such instructions;

(c) whether these instructions have yielded some good results;

(d) if so, the details thereof, State and Union Territory-wise with names of co-partners in private sectors responsible for such yield;

(e) whether some guidelines have been issued prompting involving of these co-partners in private sectors;

(f) if so, the details thereof with formalities required for joining tourism industry;

(g) whether Government propose to issue similar instructions to other States and Union Territories for promoting tourism in the country; and